Date – 4 June 2022

शस्त्र नियंत्रण कानून

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 11 दिनों के दौरान सामूहिक गोलीबारी की दो घटनाएं हुईं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों सहित 30 से अधिक लोग मारे गए।
- अमेरिका में वर्ष 2020 में कुल 24,576 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 79% (19,384) मौतें गोलीबारी के कारण हुईं।
- अमेरिका में शस्त्र विनियमन संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच विद्यमान एक साझा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है।

- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना था कि अमेरिकी संविधान में दूसरा संशोधन आत्मरक्षा में "हथियार रखने और धारण करने" के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि संघीय अदालतों ने संघीय, राज्य और स्थानीय द्वारा संभावित उल्लंघन के लिए तर्क दिया है। नियम इस अधिकार को बाधित करते हैं।

भारत में शस्त्र नियंत्रण कानून:

शस्त्र अधिनियम, 1959:

- इसका उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करना है।

भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यताएं:

- भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
- आवेदक को आवेदन से पहले पांच साल के लिए हिंसा या नैतिकता, 'अस्वस्थ दिमाग', या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को खतरे में डालने वाले किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संपत्ति योग्यता कोई मानदंड नहीं है।
- एक आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अर्थात् गृह मंत्रालय) निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से जांच के बाद आवेदक के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहता है।

अधिनियम की अन्य विशेषताएं:

- यह 'निषिद्ध हथियारों' को ऐसे हथियार के रूप में परिभाषित करता है जो या तो किसी हानिकारक तरल या गैस को छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें ट्रिगर को दबाने की आवश्यकता होती है
- यह फसल सुरक्षा या खेल के लिए कम से कम 20 इंच के बैरल वाली स्मूथबोर गन के उपयोग की अनुमति देता है।
- किसी भी संस्था को ऐसी बंदूक बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई अन्य दृश्यमान मुहर या पहचान चिह्न नहीं है।

शस्त्र अधिनियम में संशोधन:

- 2019 में संशोधित शस्त्र अधिनियम, एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर सकता है।
- लाइसेंस की वैधता को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
- इसमें सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

सजा:

- बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने, रखने या ले जाने के अपराध के लिए कारावास को 7 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है।

- यह बिना लाइसेंस वाली बंदूकों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदलने पर रोक लगाता है।
- गैरकानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण कम से कम सात साल के कारावास से दंडनीय होगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

स्वदीप कुमार

तेलंगाना स्थापना दिवस

- तेलंगाना के राज्यपाल ने तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर राज्य के लोगों को बधाई दी।

परिचय:

- 2 जून 2014 को, 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग से अलग कर बनाया गया था।

- आंध्र राज्य अधिनियम (1953) ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) से अलग कर भारत में पहला भाषाई राज्य बनाया, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) के तहत, हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक बड़ा आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंध्र राज्य के साथ मिला दिया गया था।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (2014) ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों (यानी आंध्र प्रदेश (शेष) और तेलंगाना में विभाजित कर दिया।
- **राजधानी:** हैदराबाद

सीमाएँ:

- तेलंगाना उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व दिशाओं में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है।

तेलंगाना के चार प्रतीक:

- **राजकीय पक्षी –** पलपिट्टा (इंडियन रोलर या ब्लू जे) ।
- **राजकीय पशु –** जिन्का (हिरण) ।
- **राजकीय वृक्ष –** जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरिया) ।
- **राजकीय पुष्प –** तांगेदु (टान्नर कैसिया) ।

YOJNA IAS

लोकप्रिय त्यौहार:

- उगादि, श्री राम नवमी, बोनालू, विनायक चतुर्थी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति, होली, महाशिवरात्रि जैसे हिंदू त्योहार धूमधाम, उल्लास और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं।
- पेड़ा पांडुगा के साथ दशहरा मुख्य त्योहार है।

वैश्विक मान्यता:

- मुलुगु जिले में रामप्पा मंदिर काकतीयों की विशिष्ट शैली प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की नींव "सैंडबॉक्स तकनीक" है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- निर्मल जिले में गोदावरी नदी के पार सदरमत एनीकट और कामारेड्डी जिले में पेद्दा चेरुवु नदी को विरासत सिंचाई संरचनाओं के ICID रजिस्टर में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यान:

- कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान
- महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान
- मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य:

- किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य
- एथुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य
- कवल टाइगर रिजर्व

YOJNA IAS

- लांजा मदुगु शिवराम वन्यजीव अभयारण्य
- मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य
- नागार्जुन सागर-श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य
- पाखल वन्यजीव अभयारण्य
- पोचारम वन्यजीव अभयारण्य
- प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य

अन्य पहल:

- तेलंगाना ने दूर-दराज के क्षेत्रों में टीके पहुंचाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा विकसित एक ड्रोन-आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल, आई-ड्रोन के उपयोग को मंजूरी दी है।

स्वदीप कुमार

तालिबान सरकार और भारत

- अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार भारत ने विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव 'जेपी सिंह' के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजा है।

चर्चा के क्षेत्र:

- रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फिर से शुरू करना,
- राजनयिक संबंधों को सक्रिय करना, और
- अफगान छात्रों और रोगियों के लिए वीजा जारी करना फिर से शुरू करना।

भारत द्वारा अफगानिस्तान को अब तक दी गई सहायता:

- मानवीय सहायता के मामले में, भारत ने अब तक अफगान लोगों को 20,000 मीट्रिक टन (MT) गेहूं, 13 टन दवाएं, COVID टीकों की 500,000 खुराक और सर्दियों के कपड़े भेजे हैं।
- इस सहायता को संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वितरित किया गया है, क्योंकि भारत में अफगानिस्तान में इस सहायता सामग्री को वितरित करने के लिए लोग नहीं थे।

तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर भारत का रुख:

- 'संकल्प 2593' को भारत की अध्यक्षता में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (यूएनएससी) द्वारा अपनाया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान

के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाएगा।

- भारत ने सितंबर में आयोजित 'अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति' पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में, भारत ने अफगानों को राहत सामग्री के प्रवाह में मदद करने के लिए 'काबुल हवाई अड्डे' के नियमित वाणिज्यिक संचालन को सामान्य बनाने की मांग की।
- भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान पर 'दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता' की मेजबानी की।

संबंधित मामला:

- तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तब से, देश में लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है और न ही आय का कोई साधन है। इस सर्दी में 22 मिलियन से अधिक अफगानों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सूखे ने उनके संकट को और बढ़ा दिया। ये सभी स्थितियां अफ़गानों को देश से भाग जाने या भुखमरी के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रही हैं।

अफगान स्थिरता का महत्व:

- अफगानिस्तान में तालिबान की बहाली का प्रभाव उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि में फैल सकता है।

- तालिबान के पुनरुत्थान से इस क्षेत्र में 'उग्रवाद' फिर से जीवित हो जाएगा और यह क्षेत्र 'लश्कर-ए-तैयबा', आईएसआईएस आदि के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है।
- अफ़ग़ानिस्तान में गृहयुद्ध से मध्य एशिया और उसके बाहर शरणार्थी संकट पैदा हो जाएगा।
- अफगानिस्तान की स्थिरता मध्य एशियाई देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देगी – सबसे कम दूरी के मार्ग से।
- अफगानिस्तान क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मध्य-एशिया और शेष विश्व के बीच एक सेतु का काम करता है।

भारत के लिए तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- तालिबान की अब अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
- भारत पहले ही अफगानिस्तान में भारी निवेश कर चुका है। भारत को अपनी 3 अरब डॉलर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान में सभी पक्षों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए।
- तालिबान का पाकिस्तान के साथ गहरा राजकीय संबंध बनाना भारत के हित में नहीं होगा।
- यदि भारत अभी संपर्क स्थापित नहीं करता है, तो रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के राजनीतिक और भू-राजनीतिक भाग्य-विधाता के रूप में उभरेंगे, जो निश्चित रूप से भारतीय हितों के लिए हानिकारक होगा।

- अमेरिका ने 'अमेरिका-उज्बेकिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान' के रूप में एक "क्वाड" के गठन की घोषणा की है, जिसने क्षेत्रीय-कनेक्शन पर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है – जिसमें भारत शामिल नहीं है।
- अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने का भारत का प्रयास खतरे में है।

समय की आवश्यकता:

- तालिबान द्वारा की जा रही हिंसा को रोककर अफगान नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल आवश्यकता है।
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे मध्य एशियाई संगठन में अफगानिस्तान को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।
- अमेरिका, ईरान, चीन और रूस को अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।
- शरणार्थी संकट उत्पन्न होने पर समेकित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- भारत को तत्काल पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए।

स्वदीप कुमार

स्टॉकहोम कन्वेंशन के 50 साल

- स्टॉकहोम+50 का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में हो रहा है। यह मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) की 50 वीं वर्षगांठ का उत्सव है।
- इस अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जा रहा है।
- यह ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब स्टॉकहोम घोषणा के 50 साल बाद भी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अपशिष्ट, प्रकृति और जैव विविधता के नुकसान, अन्य मुद्दों के ट्रिपल ग्रह संकट का सामना कर रही है। यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खतरा है।
- कोविड-19 महामारी से स्थायी रूप से उबरना भी एजेंडा बिंदुओं में से एक होगा।

स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में:

- 'मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' 5 जून से 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था।

- यह पृथ्वी के पर्यावरण पर इस तरह का पहला विश्वव्यापी सम्मेलन था, और इसका विषय 'केवल एक पृथ्वी' था।
- सम्मेलन का समापन स्टॉकहोम घोषणा में हुआ, जिसमें पर्यावरण सिद्धांत और पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशों के साथ एक कार्य योजना शामिल थी।

सम्मेलन के तीन आयाम थे:

- भाग लेने वाले देश "एक दूसरे के पर्यावरण या अपने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने" पर सहमत हुए।
- पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खतरे का अध्ययन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी।
- देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यूएनईपी) नामक एक अंतरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई थी।

स्टॉकहोम सम्मेलन का महत्व और परिणाम:

- वर्ष 1972 तक विश्व के किसी भी देश में 'पर्यावरण मंत्रालय' नहीं था।
- 'नॉर्वे' के प्रतिनिधि 'पर्यावरण के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने' के लिए सम्मेलन से लौटे।
- भारत ने 1985 में अपने 'पर्यावरण और वन मंत्रालय' की स्थापना की।

स्वदीप कुमार